DOI: 10.51220/hjssh.v9i1.2

Himalayan J. Soc.Sci. & Humanities Vol- 9 pp.13 - 20, December, 2014, ISSN. 0975 - 9891

नक्सलवाद देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए खतरा: एक विश्लेषण

जयवीर सिंह एवं सिरिल गोरन
राजनीति विज्ञान विभाग,
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ (उ०प्र०)
sirilgauran@gmail.com, jaivirrana64@gmail.com

Received: 19.10.2014 Revised: 2.11.2014 Accepted: 17.12.2014

ABSTRACT

प्रस्तुत अध्ययन में नक्सलवादी आन्दोलन भारत के कई प्रान्तों में तेजी से फेल रहा है। कई राज्यों में नक्सलवाद आम लोगों को गुमराह करके लाल गलियारा बढ़ाने में लगे हुये है तथा भारत की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे है। हमारी पुलिस प्रशासन का मनोबल कम हुआ हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नक्सलवादियों की राजनेताओं से साठ-गांठ भी उजागर हो चुकी है। गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, अशिक्षा का लाभ उठाकर सरकार की दूरदर्शी सोच के अभाव में नक्सलवाद पनपा है। इस विषय पर ही हमने छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ही अध्ययन क्षेत्र चुना। नक्सलवाद की वजह से देश में आम लोगों से लेकर कई राजनेताओं तक की हत्याऐं हुई। वास्तव में नक्सलवाद के उदय का प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक,आर्थिक, राजनीतिक, सामायिक एवं काफी हद तक प्रशासनिक शोषण से सम्बन्धित हैं जातीयता, क्षेत्रीयता, असंतुलित विकास, बेरोजगारी, मानसिक पिछड़ापन भी एक बड़ा मुद्दा हैं। देश में स्वाधीनता के बावजूद प्रत्येक क्षेत्र में घोर विषमता व्याप्त है, चाहे वह क्षेत्र आधारित हो, सामाजिक हो अथवा राजनीतिक, सामाजिक तौर पर तो यहाँ सदियों से वर्गीय असमानता मौजूद है। इस वर्गीय असमानता में प्रत्येक प्रकार की विषमता का बीज समाहित है। नक्सलवाद भी इस बीज से ही उपजा है।

KEY WORDS-नक्सलवाद, आन्तरिक सुरक्षा, असमानता, आन्तरिक चुनौती।

प्रस्तावना

भारत की एकता और अखण्डता के लिए विद्यमान समस्याओं में आतंकवाद, अलगाववाद के साथ नक्सलवाद एक गम्भीर चुनौती बन चुका है। विगत कुछ वर्षों तक नक्सलवाद को एक क्षेत्रीय समस्या माना जाता था लेकिन अब यह एक राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर चुका है।

नक्सलवाद क्या है

देश के अपने ही लोगों द्वारा अपनी सरकार के खिलाफ चलाये जाने वाले आन्दोलन को नक्सलवाद कहते है। इस आन्दोलन को सम्पादित करने वाले लोगों को नक्सलवादी या माओवादी की संज्ञा दी गयी है। वास्तव में नक्सलवाद कोई दार्शनिक सिद्धान्त नहीं है। यह एक हिंसक नीति है जिसमें हिंसा के माध्यम से

©SHARAD

जनता में या समाज में आतंक फैलाया जाता है। यद्यपि इसकी हिंसा क्रांति की हिंसा की परिणीति से अलग होती है, लेकिन फिर भी यह एक प्रकार से राजनीति हिंसा की अभिव्यक्ति है। सन् 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी नामक गांव में जमीन के विवाद को लेकर एक किसान पर हमले के विरोध में शुरू हुआ। इस विरोध को सी0पी0एम0 के कट्टरपंथी नेता चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल ने समर्थन दिया और 25 मई 1967 में नक्सल आंदोलन की शुरूआत की घोषणा कर दी। किसानों के साथ शामिल होकर सी0पी0एम0 के कार्यकर्ताओं ने जमींदारों पर हमले कर दिये और हिंसा भड़क उठी। चारू मजूमदार ने चीनी विचारक माओं के विचारों की वकालत की और निचले तबके से अपने साथ जुड़ने की अपील की ताकि उनकी गरीबी और बदहाली के लिये जिम्मेदार सरकार और शोषक वर्ग को उखाड़ फेंका जाये। इस आन्दोलन को गरीब किसानों और शोषितों-वंचितों का व्यापक समर्थन मिला। नक्सलियों के इस पहले विद्रोह में 11 किसान पुलिस की गोलियों का शिकार हुये। पश्चिम बंगाल की सी0पी0एम0 सरकार ने इस हिंसक आन्दोलन को दबा दिया। इससे नाराज नक्सलवादी समर्थक सी0पी0एम0 नेताओं ने 'ऑल इण्डिया कार्डिनेशन' कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी (एआईसीसीआर) का गठन किया। आन्ध्रप्रदेश में भी तेलांगाना के सशस्त्र विद्रोह का समर्थन करने वाले नेताओं ने अलग गुट बना लिया। सन् 1969 में चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल ने सीपीएम से त्याग पत्र दे दिया और लेनिन के जन्मदिन पर कोलकाता के शहीद मीनार से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के गठन की घोषणा कर दी और भारत में सशस्त्र संघर्ष के जरिये क्रांति लाने का आहवान किया देश के कई बुद्धिजीवी और युवा वर्ग का उन्हें भारी समर्थन मिला।

नक्सलवाद का सामाजिक आर्थिक पक्ष

वर्तमान में देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए नक्सलवाद एक बड़ी एवं कड़ी चुनौती के रूप में उभरा हैं, यह लोकतंत्र, कानून व्यवस्था, विकास एवं शांति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनकर विस्तार करता जा रहा हैं। नक्सलवाद का जन्म मूल रूप से आर्थिक व सामाजिक असमानता, अन्याय, अपराध असुरक्षा, दबाव, दमन एवं दहशत आदि के कारण हुआ। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में भूमि सुधार प्रक्रिया के तहत इस आन्तरिक समस्या की नींव रखी गई गरीबी व अमीरी के बीच भेदभाव एवं असमानता ने हिंसा की विश-बेल इतनी फैला दी कि वह अमरबेल बनकर भारत के अनेक राज्यों में तेजी से फैल गई। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडू राज्यों के साथ ही पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात राज्यों में भी जड़ें जमाने की ओर अग्रसर है। वस्तुस्थिति यह है कि नक्सलवाद भारत के किसी एक राज्य की समस्या नहीं है बल्कि यह देश के बड़े भू-भाग पर अपने पांव पसार चुका है। इसी कारण पूर्व प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए नक्सलवाद को देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए सबसे गम्भीर चुनौती के रूप में स्वीकार किया हैं।

सन् 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से किसान आन्दोलन के रूप में शुरू हुए, इस संघर्ष को सन् 1967 में नक्सली आन्दोलन कहाँ गया। नक्सलवाद का उदय तीन विचारधारा, तीन गांव, तीन लक्ष्य एवं तीन नेताओं के साथ सम्बद्ध है-

तीन नेता	-	कान्यू सान्याल, चारू मजूमदार व जंगल संथाल
तीन गांव	-	नक्सलवाड़ी, खारीबाड़ी तथा फांसीदेवा

तीन उद्देश्य	-	खेत जोतने वालों को खेत का हक मिले
	-	विदेशी पूंजी की ताकत समाप्त की जाये।
	-	वर्ग एवं जाति के विरूद्ध संघर्ष हो।
तीन विचार धारायें	-	सी0पी0आई0 (मार्क्सवादी लेनिनवादी माले)
		पी0डब्ल्यू0जी0-(पीपुल्स वार ग्रुप)
	-	एम0सी0सी0 (माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टर)

हिंसा किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है, न इसे किसी तरह उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन सभ्य समाज की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उन कारणों का निवारण करें, जिससे यह हिंसा पैदा होती है, बहरहाल नक्सलवादी कहीं के भी हो उनका धर्म हिंसा ही होता है और वे हिंसा के माध्यम से अपनी बात मनवाना चाहते हैं किन्तु हिंसा को कभी भी समर्थन नहीं मिल सकता। नक्सलवाद से निपटने का अधिकार तो हर राज्य सरकार का है, लेकिन जब स्थिति काबू से बाहर हो जाये तो केन्द्र से सहायता की मांग की जाती है। केन्द्र और राज्य सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सामंजस्य के साथ मिलकर नक्सलवाद के खिलाफ लड़े तो नि:सन्देह इनका निराकरण कर आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हुए कर सामाजिक एवं आर्थिक विकास किया जा सकता है।

नक्सली समस्या मूलत: सामाजिक-आर्थिक विकास और शोषण, उत्पीड़न से जुड़ी समस्या है, इसलिए बन्दूक और सैनिक शक्ति के बल पर इसका समाधान सम्भव न होगा। इसके लिए विकास के लाभ और न्याय को निचले स्तर तक पहुंचना होगा। राज्य सरकारों को भूमि सुधार कार्यक्रमों को तेजी से लागू करना होगा। राष्ट्रीय जनजातीय नीति में आदिवासियों के अधिकारों की समुचित व्यवस्था करने के साथ पिछड़े तथा दूरदराज के इलाकों में युवा वर्ग को रोजगार मुहैया कराना होगा। सम्प्रति सरकार ने उक्त समस्या से निटपने के लिए एक व्यापक चौदह सूत्रीय योजना तैयार की है। इन सबको सही सकारात्मक दशा-दिशा मिले इसके लिए सरकार को बातचीत की अच्छी पहलकदमी की शुरूआत करनी होगी साथ ही माओवादियों को पहले हथियारों का समर्पण करने के लिए राजी करना होगा। सरकार ने यदि सच्चे मन से उपरोक्त तथ्यों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना आरम्भ किया तो नक्सली वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल हो सकते है और आपसी भाईचारे के साथ मुख्य धारा में मिलकर आवाम को नया अहसास देंगे। सम्प्रति नक्सलवाद सम्बन्धी समस्या पर इसके पैदाइशी स्वरूप से वर्तमान परिवेश तक समीक्षात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही बात सामने आती है कि राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग विद्रोही करार देने वाले ये नक्सली सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी किए हुए हैं।

सलवा जुडूम आन्दोलन से गुस्से में नक्सलवादी

नक्सलवादी इस आन्दोलन से नाराज है। सलवा जुडूम आन्दोलन की शुरूआत महेन्द्र कर्मा ने सन् 2005 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके से की थी। सलवा जुडूम शब्द का अर्थ है-''शान्ति मार्च'' नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार इसे अप्रत्यक्ष तौर पर लाभ पहुंचा रही है। धीरे-धीरे बड़ी तादाद में आदिवासी इस आन्दोलन से जुड़ रहे है। सेना तैयार की जा रही है। सेना में नक्सलवाद के प्रभाव

वाले इलाकों के युवाओं को खासतौर से शामिल करने का अभियान चलाया जाता है। महाराष्ट्र में तो सरकार आदिवासियों की बाटालियन खड़ा करना चाहती है। नक्सलवादियों से निपटने के लिए ही सरकार सलवा-जुडूम आन्दोलन को जारी रखना चाहती है, क्योंकि इसमें 18 वर्ष के लड़के व लड़कियों को सेना में रखा जाता है। उन्हें अप्रत्यक्ष तौर पर बन्दूकें चलानी सिखायी जाती हैं तथा सैलरी दी जाती हैं जिससे माओवादियों का सामना आदिवासी सेना आसानी से कर सके और आदिवासी बनाम आदिवासी लड़ाई जारी रह सके।

माओवादी बनती महिलाऐं

रिबैका (आदिवासी) लड़की है वह भारत के पूर्वी प्रदेश उड़ीसा में माओवादी के बगावत करने वाले दल के स्थानीय एरिया कमाण्डर की बाडीगार्ड है। माओवादी जो नक्सलियों के नाम से भी जाने जाते है भारत के मध्य और पूर्व में बीते 40 सालों से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे है। वे गरीबों के लिये भूमि व नौकरी की मांग करते है, उनका उददेश्य भारत की अर्द्धऔपनिवेशक, अर्द्धसामन्ती व्यवस्था को सत्ता से बेदखल कर साम्राज्यवाद की स्थापना करना है।

नक्सलवादी अध्ययन क्षेत्र

नक्सलवाद आज भारत की बड़ी समस्याओं में से एक है। इसकी विरोधाभासी प्रकृति और सरकारों के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने इसे और खतरनाक बना दिया है जहां बुद्धिजीवी नक्सली आन्दोलन की आरम्भिक विचारधारा से सहानुभूति रखते है, वही वर्तमान में भटके हुये नक्सलियों द्वारा की जा रही हिंसा के प्रति आक्रोशित भी है। आज देश के 20 राज्यों के 200 से ज्यादा जिले नक्सली हिंसा की चपेट में है। जिसमें गम्भीर रूप से प्रभावित जिले 51, सामान्य रूप से प्रभावित राज्य 15, सीमान्त रूप से प्रभावित जिले 62 व लक्षित जिले-34 है (ये आंकड़े 2012 तक के है।) अब तक हजारों लोग इस हिंसा का शिकार बन चुके है। किसान आन्दोलन से शुरू होकर आज यह आतंकवादियों के नक्शे कदम पर चल पड़ा हैं। स्थिति इतनी विकराल है कि पिछले कई सालों में ही माओवादियों ने 1500 से अधिक लोगों का अपहरण किया और इनमें से 328 को मौत के घाट उतार दिया। छत्तीसगढ़ के नवसृजित जिले सुकमा के कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन का अपहरण और इससे एक ही दिन पहले बीजापुर के विधायक महेश गागड़ा और कलेक्टर रजत कुमार का बारूदी सुरंग विस्फोट में बचना ये सभी नक्सली आक्रमण है। माओवादी समस्या से निपटने में एक बड़ी चुनौती नक्सलियों द्वारा बंधक बनाये जाने के इन तरीकों से निपटना है। केन्द्र सरकार अब तक इस समस्या का हल ढूंढ नहीं पाई।

राज्यों में नक्सलवाद

नक्सलवाद की चपेट में देश के करीब 20 राज्यों के 280 से ज्यादा जिले आ चुके है जो कुल भारतीय भूमि का लगभग 40 फीसदी हिस्सा है। जिनमें से छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा, महाराष्ट्र,आन्ध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल सर्वाधिक नक्सलवाद प्रभावित राज्य है पश्चिम बंगाल में पश्चिमी मिदनापुर का लालगढ़ जिला सबसे अधिक नक्सलवाद से प्रभावित जिला है। नक्सलवादी संगठन अपने कार्यवाहियों को अंजाम देने के लिए मुख्यत: निम्न तरीकों का प्रयोग कर रहे है-

1. संचार सेवा नष्ट करना इससे न केवल जनता का ध्यान उनकी ओर आकृर्षित होता है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त हो जाती है। इसके अन्तर्गत रेलवे की पटरी हटा देना, वद्युत पोल, विद्युत ग्रहों को उड़ा देना, स्टेशन व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बम रखना आदि तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है।
2. भीड़भाड वाले इलाको में गोली चला देना जिसमें लोगों की जान चली जाती है। और निर्दोश लोग मारे जाते है।
3. सरकारी नौकरशाहों, मन्त्री, विधायकों व बड़ी-बड़ी नामचीन हस्तियों का अपहरण कर उनसे मांगे मनवाना, मांग पूरी न होने पर बन्धक बनाना या हत्या कर देना वहीं बड़े-बड़े उद्योगों से वसूली करना प्रमुख कार्य है।

शोध प्रारूप

आंकड़ों के आइने में नक्सलवादी हिंसा

सन् 2012 जुलाई तक माओवादी हिंसा की 811 घटनाओं में सुरक्षा बलों के 80 कर्मियों सहित 270 लोग मारे गये हैं। पिछले वर्ष 14 जून तक माओवादी हिंसा की 1025 घटनाओं में सुरक्षा बलों के 177 कर्मियों सहित 473 लोगों की मौत हुई थी। जाहिर तौर पर आंकड़े कुछ भी कह रहे हो किन्तु यह साफ दिखता है। इस समय नक्सलियों ने उड़ीसा, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ को अपना मुख्य निशाना बना रखा है। माओवाद प्रभावित राज्यों की छत्तीसगढ़ से लगी 4000 वर्ग किलोमीटर की सीमा पर चौकसी बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय पुलिस बलों और केन्द्रीय बलों में और बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। साथ ही पुलिस बलों को यह भी प्रेरित करने की जरूरत है कि वे आम जनता के मित्र की तरह पेश आऐं और जनता के बीच विश्वास बहाली का काम करें। क्योंकि जनसहयोग के बिना यह आपरेशन सफल नहीं हो सकता।

आम विचारों में नक्सलवाद

नक्सलवाद के बारे में विद्वानों के विचार निम्न है-

1. नक्सलवाद आन्तरिक सुरक्षा के लिये आतंकवाद से भी बड़े खतरे के रूप में उभरा है और सामाजिक आतंकवाद का नया खौफ पैदा कर रहा है। इसकी झलक छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अपरहण मामलों में देखने को मिलती हैं सरकार के आत्मसर्मपण के लिये खुद सरकार की जनविरोधी नीतियां ही जिम्मेदार है। इसी से नक्सलवाद के फलने-फूलने का वैचारिक आधार तैयार हुआ है। जल, जंगल, जमीन की लड़ाई को सरकार ने अपनी पूंजीपरस्त नीतियों से नई जमीन प्रदान की है। लड़ाई की यह नई जमीन सर्वागीण विकास के नारे की विफलता के कारण तैयार हुई।
2. नक्सलवादियों के बढ़ते हौसले के पीछे देश की राजनीतिक स्थितियों है, हर बार नक्सलियों की मांगों को मानना पड़ता है कम से कम अब नीति निर्धारकों से यह उम्मीद करना उचित होगा कि बंधक समस्या के सम्बन्ध में एक बाध्यकारी और सर्व-स्वीकार्य नीति बनाई जाये। सबसे पहले सरकार यह घोषित कर दे कि किसी भी हालत में अपहरणकर्ताओं से कोई बात नहीं की जायेगी, जब भी किसी अपहरण की खबर मिलेगी, बिना किसी नुकसान की परवाह किये सीधे आक्रमण किया जायेगा। अगर सम्भव हो तो यथाशीघ्र कानून बनाकर तथा उसी आधार पर लोकमत के निर्माण के सरकार लिए पहल करें।

3. भारत का राजनीतिक नेतृत्व और भारत की नौकरशाही देश में बढ़ते नक्सलवाद को लेकर कितनी लापरवाह और संवेदनहीन है वर्ष 2005 में जबसे नक्सलवाद ने भारत में अपनी पैठ बनानी शुरू की, सरकारी दावों के बावजूद भारत में इनकी पकड़ बढ़ती जा रही है। आज भारत के करीब 600 जिलों में से 60 जिलों पर नक्सलियों का वर्चस्व है यहां सिर्फ नक्सलियों की ही चलती है। 2010 में सबसे ज्यादा नक्सली हादसे (2,212) भारत में हुये है। जिसमें पुलिसकर्मी सहित एक हजार से अधिक लोग मारे गये है जो की बहुत बड़ी संख्या हैं गृहमंत्री रह चुके पी0 चिदम्बरम ने नक्सलवाद से निपटने के लिए एक नीति बनाई जिसका नाम ऑपरेशन ग्रीन हंट रखा था। इस रणनीति के मूल बिन्दु थे कि पहले आक्रामक रूख अपनाकर नक्सली वर्चस्व वाले इलाके को वापस अपने कब्जे में लो, इनमें सक्षम प्रशासन लागू करो और फिर इनका पूर्ण विकास करो। यह नीति सामरिक रूप से बहुत सही थी, जब तक सरकार आक्रामक नहीं होगी, नक्सलियों को यह संदेश कैसे जायेगा कि सरकार के पास नक्सलियों को समाप्त करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति है और सरकार हर कीमत पर उन्हें नेस्तनाबूद करके रहेगी।

4. नक्सलवादियों के लिए आम जनता की एक राय यह है कि अपहरण और हत्या में लिप्त माओवादी केवल आतंकी है दूसरी राय यह भी है कि माओवादी वास्तव में शोषितों के हक की लड़ाई लड़ रहे है। आदिवासी क्षेत्रों में आज भी ऐसे गांव मौजूद है जिनके बारे में केन्द्र या राज्य सरकारों को कुछ भी मालूम नहीं है इन गांवों में ऐसे आदि वासी रहते है, जिन्होंने कभी बिजली, स्कूल, अस्पताल और मशीन के बारे में नहीं सुना है। ये आदिवासी इसी सोच को लेकर जन्म लेते और मरते है कि माओवादी ही सरकार है, वे ही इनकी जरूरतों को पूरा करते है। बोडीगुड्डा एक ऐसा ही गांव है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैले घने जंगलों के बीच में है।

5. नक्सलवाद समाज को बदलने वाली एक राजनीतिक विचारधारा है देश में स्थितियाँ इस कदर विषम हो गई है कि 76 प्रतिशत लोग रोजाना बीस रूपये से कम पर गुजारा कर रहे है। नक्सलवाद प्रभाव के विस्तार को रोकने के लिए सरकार पहले इसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्या के रूप में देखती थी, वह यह मानकर चलती थी कि जिन इलाको में पिछड़ापन है और समाज का जो हिस्सा बेहद पिछड़ा है उसके बीच में इनका प्रभाव होता है। देश के कई हिस्सों में ये देखा जा चुका है कि तमाम तरह की योजनाओं को लागू करने का दावा करने के बाद भी नक्सलवाद के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म नही किया जा सका है।

परिणाम

नक्सली मांगों को पूरा करने के लिए करते है अपहरण व हत्याऐं

माओवादी अपहरण इसलिए करते है ऐसा करने से वे अपनी मांगों को मनवा सकते है। उड़ीसा में इतालवी नागरिको को रिहा कराने के लिऐ मुख्यमन्त्री बीजू पटनायक ने 27 माओवादियों को जेल से रिहा किया था। इसके अलावा माओवादियों का मानना रहा है कि अपहरण व हत्याओं के जरिये वे अपनी समस्याओं को आसानी से जनता तक पहुँचा सकते है। माओवादी अक्सर अप्रैल-मई में अपना सम्मेलन का जंगलों में आयोजित करते हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी आगे की रणनीति बनाने के लिए एकत्र होते है। ऐसे मौके पर प्रशासन की निगाह से बचने के लिए अपहरण और अन्य वारदातों को अंजाम दिया जाता है, ताकि प्रशासन इन वारदातों में उलझा रहे और सम्मेलन पर ध्यान न दिया जाये।

उददेश्य

नक्सलियों की माँगे

सरकार के सामने नक्सलियों की ओर से तीन मांगे रखी गई थी, एक तो अलग तेलंगाना राज्य का निर्माण जो अब हो गया है, दूसरा सामाजिक-आर्थिक समस्या का निराकरण और तीसरा राज्य की योजनाओं से विश्व बैंक को अलग रखना। सरकार ने केवल अब तक एक ही मांग को पूरा किया है बाकी मांगे ऐसी ही प्रश्नसूचक बनी हुई है।

नक्सलवादी आन्दोलन के बढ़ने के कारण

1.असन्तोष की भावत्ता का लगातार व्याप्त होना और वैधानिक तरीके से इसका निराकरण न हो पाना।

2.भ्रष्टाचार की समस्या।

3.नक्सल प्रभावी क्षेत्रों को सुख-सुविधाओं से वंचित रखना।

4.विदेशी हथियारों का भारत में प्रवेश होना।

5.विदेशी संस्थाओं का नक्सलवादियों को सहयोग प्राप्त होना।

6.बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी व चिकित्सा सेवा का अभाव होना।

7.सरकार द्वारा पक्षपातीय व भेदभावपूर्ण नीतियों का बनाया जाना।

8.राज्य सरकारों का भी नक्सल प्रभावी क्षेत्रों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाना।

9.अमीर-गरीब के बीच की बढ़ती खाई या भू-स्वामियों तथा भू-मजदूरों के बीच का आर्थिक असन्तुलन भी नक्सलवाद का प्रमुख कारण है।

10.मानवाधिकारों व जनमत के प्रति संवेदनशीलता के कारण सशक्त कार्यवाही सम्भव न हो पाना।

11.समाज में हो रहे तीव्र सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन लोगों में व्यक्तिगत असुरक्षा की भावना पैदा कर रहे है जिसके कारण व्यक्ति हिंसक साधनों की ओर सहज ही आकर्षित होते है।

नक्सलवाद को दूर करने के सुझाव

1.नक्सलवादी प्रभावी क्षेत्रों में नवयुवकों के लिए सीधी भर्ती की जायें।

2.प्राकृतिक खनिज पदार्थों की लूट बन्द हो।

3.भ्रष्टाचार को खत्म किया जाये जिससे नक्सल प्रभावी क्षेत्रों का सरकारी मशीनरी में विश्वास पैदा हो।

4.गरीब को नक्सल प्रभावी क्षेत्रों से दूर करने के लिए व्यवहारिक उपाय किये जाये।

5.नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाये और वहां के लोगों की सीधी जनसहभागिता हो।

6.लोगों का शोषण बन्द किया जाए।

7.नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में संचार की व्यवस्था की जाये।

8.नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया जाये, खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति की जाये।

9.नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में प्रत्येक स्तर की शिक्षण संस्थाऐं खोली जाये।

10.नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में आवागमन के लिए व समान ढोने के लिए परिवहन व्यवस्था का विकास किया जाये।

11.नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में पुलिस फोर्स को आम लोगो के बीच में समन्वय रखना चाहिये।
12.नक्सल प्रभावी क्षेत्रों के लोगों को खुला मंच मिले जिससे वे अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सके।
13.नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधा की आपूर्ति की जाये साथ ही पेयजल, खाद्यान्न व बिजली की आपूर्ति की जाये।
14.नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाये।
15.नक्सल प्रभावी क्षेत्रें में कृषि का विकास किया जाये जिससे अन्न का उत्पादन किया जा सके।
16.विदेशियों से सम्पर्क को बन्द किया जाये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1.दूबे, अभय कुमार (2008) 'क्रांति का आत्म संघर्ष: नक्सलवादी आन्दोलन का बदलता चेहरा,' समकालीन प्रकाशन, पटना।
2.पटनायक, एस0एस0 (2002), 'माओइस्ट इमरजेन्सी इन नेपाल: इक्जामिंन सोशियो-इकोनॉमी ग्रिवेन्स एण्ड पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन,' स्त्रतेजिक एनालसिस, वाल्यूम-26 नं0 1, जनवरी-मार्च, पृ0-119
3.'नक्सलवाद की खिलाफ सेना का इस्तेमाल न हो', वेलफेयर ऑफ सर्विंग सोल्जर एसोसिशन के अध्यक्ष कर्नल वी0के0 अग्रवाल की एक रिपोर्ट-अमर उजाला, 22 जुलाई, 2010
4.सिंहप्रकाश सिंह (2002), 'द माओइस्ट इन्सरजेन्सी इन इण्डिया एण्ड नेपाल-डायलॉग', क्वार्टरली जनरल-आस्था भारती, वाल्यूक 4 नं0-2, अक्टूबर-दिसम्बर।
5.यादव, मनोज कुमार एवं कुमार अजय (2011), 'नक्सलवाद का प्रसार एवं भारत की आन्तरिक सुरक्षा प्रभाव' सुरक्षा चिन्तन, वाल्यूम नं0-2।
6.प्रसाद राजेन्द्र (2002), इण्डिया सिक्योरिटी इन ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी, डोमिनेन्ट पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
7.मोहन राम (1991) 'माओइज्म इन इण्डिया', विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
8.राघवन वी0आर0 (2010), 'द नक्सल थ्रेट: कॉजेज, स्टेट रिस्पान्स एण्ड कान्सिक्वेन्स-ए0बी0सी0 पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
9.बनर्जी सुमनत (1980), 'इन द वेक ऑफ नक्सलवारी: ए हिस्ट्री ऑफ द नक्सलाइट मूवमेन्ट इन इण्डिया,' सुवर्णरेखा पब्लिशिंग हाउस, कोलकाता।
10.चन्द्रन शुभ एण्ड जोसेफ मल्लिका (2010), 'इण्डिया: द नक्सलाइट मूवमेन्ट, सर्चिंग फॉर पीस इन सेन्ट्रल एण्ड साउस एशिया,' जेड बुक्स पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
11.शुक्ल कृष्णानन्द (2011), 'नक्सलवाद एवं आन्तरिक सुरक्षा,' सन राईज पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
12- Ray Rabindr (1988)] The Naxalites and Their Ideology, Oxford University Press, New Delhi.
13-Ghosh Shankar, (1974) The Naxalite Movement : A Maoist Experiment Calcutta, Firma K.L. Mukhopadhyay.